Maharashtra Housing and Area Development Authority during the last three years to provide civic amenities in slums located in Maharashtra and on the Central Government land like Defence lands, Airport area lands, etc; and

(b) if so, the details thereof and the progress made in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) Government of India is not separately providing any fund for provision of basic amenities to the slums located on their lands in Bombay. The State Government has reported that in consultation with the Central Ministries, they have decided to provide, in appropriate cases, basic amenities in slums on Central Government lands also, in Bombay, under the State sector Scheme of Environmental Improvement of Urban Slums.

Financial assistance to Cooperative Societies

501. SHRIMATI SUDHA VIJAY JOSHI : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the details of the financial help provided by NABARD during the last two years and the current year to Cooperative Banks and Cooperative Societies in Maharashtra to help needy farmers in their agricultural operations;

(b) whether NABARD is insisting on certain conditions to be fulfilled by the above Cooperative bodies to become eligible for the financial help from NABARD and these bodies are finding it difficult to fulfil the same; and

(c) whether the above matter is being examined to facilitate the flow of finance from NABARD to the cooperative bodies referred to above?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHYAM LAL YADAV): (a) During the two years and the current financial year, NABARD provided refinance facility to the Maharasthra State Cooperative Bank for seasonal agricultural operations as listed below:

	(Rs. in crores)
1987-88	92.65
1988-89	129.35
1989-90 . . . . . (Upto June 89)	60.00

(b) and (c) For availing of refinance from NABARD Cooperative Banks are required to comply with the regulations/instructions of RBI/NABARD relating to issue and repayment of loans and interest rates thereon, conversion/rescheduleement/deferment of loans or other reliefs, besides the usual criteria of eligibility regarding overdues and compliance of Sec. 11 of the Banking Regulations Act, 1949. The problem of the Maharashtra State Cooperative Bank was considered by NABARD and their refinance facility has been extended on furnishing necessary undertaking to follow the above conditions.

दिल्ली के लिए दूध की खरीद

502. **श्री हरि सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार किन किन पड़ोसी राज्यों से दिल्ली में दूध की खपत के लिए दूध खरीदती है ;

(ख) इस दूध की, राज्यवार, मात्रा कितनी है ;

(ग) पड़ोसी राज्यों की किन किन दुग्ध एजेंसियों से केन्द्रीय सरकार दूध खरीदती है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार दूध की उक्त मात्रा को खरीद के लिए प्रति वर्ष कितनी धनराशि अदा करती है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (घ) 1988-89 के दौरान डेरी संघों से दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी, दिल्ली द्वारा खरीदे गए दूध के ब्यौरे और किए गए भुगतान को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(मात्रा लाख कि० ग्रा० में)
(लाख रुपये में)

क्र० सं०	राज्य संघ	दिल्ली दुग्ध योजना		मदर डेरी		
		मात्रा (कि० ग्रा०)	राशि (रुपये)	मात्रा (कि० ग्रा०)	राशि (रुपये)	
1	उत्तर प्रदेश	44	255	140		
2	राजस्थान	78	400	181		
3	पंजाब	23	119	139		
						3765
4	मध्य प्रदेश	42	205	46		
5	हरियाणा	3	16	7		
7	गुजरात	—	—	258		

मध्य प्रदेश में खेती लायक भूमि पर खेती न किया जाना

503. **श्री हरि सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में उपलब्ध खेती लायक अधिकांश भूमि पर खेती नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार उस भूमि पर खेती आरंभ करने के लिए क्या उपाय कर रही है?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकार द्वारा प्राप्त किये गए दूध का भुगतान

504. **श्री हरि सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूध की कीमतों में वृद्धि के कारण केन्द्रीय सरकार ने बढ़ी हुई कीमतों के आधार पर 1988-89 में प्राप्त किये गए दूध की बकाया राशि का भुगतान किया है; और